



अधिकतम : 26°C
न्यूनतम : 12°C

खबरें सुपाता नहीं, छापता है

शाह टाइम्स

देहरादून, शक्रवार 21 नवम्बर 2025 देहरादून संस्करण: वर्ष 25 अंक 104 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00



विस्तृत खबरों के लिए QR कोड स्कैन करें।
मुफ्त पढ़ें E-paper

shahtimes2015@gmail.com

मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 1 विक्रमी सप्तम 2082

29 जमादिउलला 1447 हिजरी

नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वानी, पुरादाबाद, बरेली, मेठ व लखनऊ से प्रकाशित



संयुक्त राष्ट्र में तत्काल सुधार की जरूरत: ओम बिरला
पेज 2



दीक्षा डागर ने डेफ्लॉपिक्स में लगातार गोल्ड मेडल जीता
खेल टाइम्स



एसआईआर: सिर्फ आरोप से काम नहीं चलेगा
समाप्तकारी



अमेरिकी रिपोर्ट में दावा: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया
पेज 12

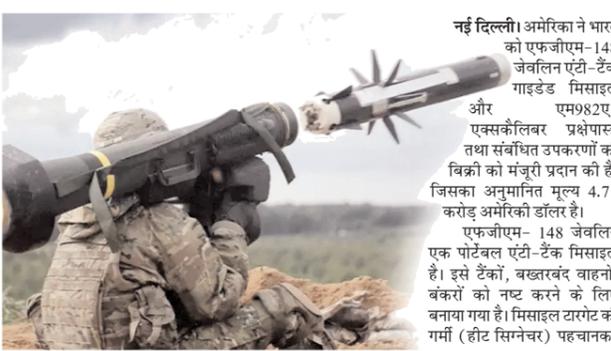
संक्षिप्त समाचार

ईडी ने क्यूआर कोड सत्यापन किया शुरू
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नाम पर धोखाधड़ी और जबरन वसूली के लिए नकली समन भेजे जाने की बढ़ती खबरों के बीच ईडी ने नागरिकों को समन नोटिस की असलियत सत्यापित करने में मदद करने के लिए नए तरीके लागू किए हैं। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को अपने आधिकारिक अकाउंट के जरिए इसकी घोषणा की। नकली ईडी समन असली नोटिस जैसे ही होते हैं, जिससे पाने वालों के लिए सही और गलत के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए ईडी अब सिस्टम से बनने वाले समन जारी कर रहा है, जिसमें एक क्यूआर कोड और एक यूनिक पासकोड होता है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किए गए समन को उन पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करके या आधिकारिक ईडी वेबसाइट पर जाकर सत्यापित किया जा सकता है। ईडी ने यह भी साफ किया कि वह डिजिटल या ऑनलाइन गिरफ्तारी नहीं करता है। ईडी ने नागरिकों को नकली लोगों से सावधान रहने की सलाह दी है। ईडी ने नागरिकों से अपील है कि वे कोई भी कदम उठाने से पहले सावधान रहें और किसी भी सदिग्ध समन को सत्यापित करें, ताकि वे ईडी अधिकारी बनकर धोखा देने वालों का शिकार न बनें।

एसआईआर: भारत से रोज 150 अवैध बांग्लादेशी लौट रहे
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ ने दावा किया है कि बॉर्डर पार करने की कोशिश करने वाले अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ गई है, यह वापसी राज्य में स्पेशल इंटीग्रेटेड रिजर्व (एसआईआर) से जुड़ी है। बीएसएफ के एक अधिकारी के मुताबिक नॉर्थ 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा में बॉर्डर के बिना फॉसिंग वाले हिस्सों से लौटने की कोशिश कर रहे बांग्लादेशी इमीग्रेंट्स के फ्लो में क्वॉटम जंप देखा गया है। बीएसएफ अधिकारी ने बताया कि पहले ऐसे मामले मुश्किल से डबल डिजिट में आते थे। अब यह आंकड़ा हर दिन लगातार तीन डिजिट में है। बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने कहा कि चेक पोस्ट पर छोटे और बड़े सामान लेकर लोगों को लाइन लग रही है, जो खुलेआम मान रहे हैं कि वे बांग्लादेशी हैं और सालों पहले गैर-कानूनी तरीके से भारत में आए थे।

वायुसेना के मानव रहित विमान को आपात स्थिति में उतारा
जैसलमेर। राजस्थान में जैसलमेर के सीमावर्ती रामगढ़ क्षेत्र में गुरुवार को भारतीय वायुसेना के एक मानव रहित विमान को तकनीकी खराबी के कारण एक खेत में आपात स्थिति में उतारना पड़ा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इससे किसी प्रकार के जानमाल की हानि की सूचना नहीं है। मानव रहित विमान अपने नियमित अभ्यास उड़ान पर था। घटना की जानकारी मिलने पर वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही सूचना मिलने पर पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर जांच पड़ताल शुरू की।

अमेरिका भारत को 100 टैंक किलर मिसाइल देगा



नई दिल्ली। अमेरिका ने भारत को एफजीएम-148 जेवेलिन एंटी-टैंक मिसाइल देगा।

नई दिल्ली। अमेरिका ने भारत को एफजीएम-148 जेवेलिन एंटी-टैंक मिसाइल देगा। एक्सकैलिवर प्रक्षेपास्त्र तथा संबंधित उपकरणों की विक्री को मंजूरी प्रदान की है, जिसका अनुमानित मूल्य 4.71 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। एफजीएम-148 जेवेलिन एक पोर्टेबल एंटी-टैंक मिसाइल है। इसे टैंकों, बख्तरबंद वाहनों, बंकरों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। मिसाइल टारगेट की गर्मी (हीट सिग्नेचर) पहचानकर

टारगेट की गर्मी पहचानकर हमला करती है, कुल 775 करोड़ डॉलर की डील
भारत को 4.71 करोड़ डॉलर की मिसाइलें, प्रोजेक्टाइल की विक्री को दी मंजूरी

उस पर हमला करती है। इसकी 2500 मीटर रेंज है। घुए, धूल या खराब मौसम में भी टारगेट को

बैंगलुरु में एटीएम कैश वैन से सात करोड़ की लूट

बैंगलुरु। बैंगलुरु में बदमाशों ने एक एटीएम कैश वैन से 7 करोड़ रुपये लूट लिए। घटना बुधवार दोपहर 12:30 बजे की है। बदमाशों ने खुद को भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकारी बताकर कैश वैन को रास्ते में रोक लिया और कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस को वैन बाद में जयदेव डेयरी सर्कल फ्लाईओवर के पास मिली। पुलिस ने डाइवर, दो सुरक्षकर्मियों और एक कैश डिपॉजिटर को पृछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वैन सीएमएस

बदमाशों ने RBI का अधिकारी बनकर की वारदात

कंपनी की है। पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि सीएमएस के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी सदिग्ध मानी जा रही है। मामला सिद्धापुर पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है। सीएमएस के ऑफिस से वैन सुबह 9.30 बजे एचडीएफसी बैंक की ओर रवाना हुई थी।

राज्यपाल विधानसभा से पारित बिलों को न लटकाएं: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने कहा: बिल मंजूर करें, लौटाएं या राष्ट्रपति को भेजें

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम संवैधानिक फैसले में गुरुवार को कहा कि राज्य के राज्यपाल राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल तक लटका नहीं कर सकते। न्यायालय ने हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि वह संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपालों को मंजूरी देने या न देने के लिए जरूरी समयसीमा तय नहीं कर सकता, लेकिन राज्यपाल अनिश्चितकाल तक किसी भी विधेयक को नहीं रोक सकते। हालांकि इसमें स्पष्ट किया गया है कि लंबे समय तक, बिना किसी वजह के मंजूरी नहीं दिए जाने के मामलों में न्यायालय विधेयक को प्राथमिकता को जांच किए बिना एक निश्चित अवधि में फंसला करने का निर्देश देते हुए



नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को साफ किया कि आरक्षक अपील विधेयक (आईटीए) जैसे अधिकरण में तकनीकी सदस्य के तौर पर नियुक्त किए गए चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) को कम से कम 25 साल का अनुभव होना जरूरी नहीं है।

बेल्जियम कोर्ट नौ दिसम्बर को प्रत्यर्पण के खिलाफ चोकसी की अपील सुनेगा

नई दिल्ली। भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की ओर से अपने प्रत्यर्पण को चुनौती देने के मामले की सुनवाई 9 दिसम्बर को बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ कैसेशन के समक्ष होगी। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। चोकसी ने बेल्जियम की शीर्ष अदालत में एटवर्प अपील न्यायालय के 17 अक्टूबर के फैसले को चुनौती दी है। इस

मेहुल चोकसी ने बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट में फैसले को दी थी चुनौती
फैसले में भारत की ओर से उसके प्रत्यर्पण के अनुरोध को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया गया था। एडवोकेट जनरल हेनरी वेंडरलिनडन ने कहा कि कोर्ट ऑफ कैसेशन 9 दिसम्बर को मामले की सुनवाई करेगा।

को अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 को रद्द करने वाले अपने फैसले में वकीलों को दी थी। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के वकील के पीठ के सामने यह मामला उठाए जाने पर यह स्पष्टीकरण सामने आया। वकील ने बताया कि न्यायालय ने अधिकरण में नियुक्त किए गए वकीलों को कम से कम 50 साल की उम्र की जरूरत को खत्म कर दिया था, लेकिन सीए के लिए 25 साल के अनुभव को जरूरत, जो असल में पात्रता को लगभग 50 साल तक बढ़ा देती है, पर ध्यान नहीं दिया गया। राष्ट्रपति को राज्यपाल की तरफ से भेजे गए किसी भी बिल पर तीन महीने के शेष पृष्ठ दो पर

प्रियंका गांधी के पति पर ईडी ने कसा शिकंजा

रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल



नई दिल्ली। ईडी ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के विजनेसमैन पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला ब्रिटेन के आर्म्स डीलर संजय भंडारी के साथ सदिग्ध लेनदेन से जुड़ा है। चार्जशीट दिल्ली की राजद एन्व्यू कोर्ट में दाखिल की गई है। इस मामले में पीएमएलए के तहत वाड्रा का बयान जुलाई में दर्ज किया गया था। ईडी का दावा है कि वाड्रा और भंडारी के बीच वित्तीय लेनदेन की कड़ियां मिली हैं, जिनमें विदेशी प्रोपर्टी और फंड ट्रांसफर की जांच भी शामिल है। ईडी ने चार्जशीट में वाड्रा को 9वें नंबर का आरोपी बनाया गया है। अब इस मामले पर अदालत 6 दिसम्बर को विचार करेगी। वाड्रा के खिलाफ यह मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा आरोपपत्र है। जुलाई में, ईडी ने हरियाणा के शिकोहपुर में एक जमीन सौदे में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी वाड्रा के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। संजय भंडारी हथियार डीलर

नीतीश ने 26 मंत्रियों के साथ सीएम पद की ली शपथ

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों के साथ गुरुवार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में शपथ ली, जिनमें भाजपा के 14, जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के आठ, लोक जनशक्ति पार्टी (राजद) के दो और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) तथा हिंदुस्तानी आवाज मोर्चा (हम) के एक-एक मंत्री शामिल हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने श्री कुमार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। श्री कुमार मंत्रिमंडल में सर्वाधिक 14 मंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार

भाजपा के 14 विधायक बने मंत्री

सिन्हा, मंगल पाण्डेय, पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, डा. दिलीप कुमार जायसवाल, नितिन नवीन, पूर्व केन्द्रीय मंत्री राम कृपाल यादव, संजय सिंह (राजद) तथा हिंदुस्तानी आवाज मोर्चा (हम) के एक-एक मंत्री शामिल हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने श्री कुमार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। श्री कुमार मंत्रिमंडल में सर्वाधिक 14 मंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार

पढ़े-लिखे आतंकी ज्यादा खतरनाक: दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब पढ़े-लिखे आतंकी बन जाते हैं तो वे आतंकीकरण के लिए अधिक खतरनाक हो जाते हैं। पुलिस ने कहा कि डॉक्टरों और इंजीनियरों के लिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना अब एक टैंड बन गया है। ये लोग सरकारी पैसों का इस्तेमाल करके पढ़ाई करते हैं फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में शरजील इमाम के भड़काऊ भाषणों के वीडियो पेश किए। वीडियो में शरजील इमाम नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देते हुए दिख रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इन भाषणों से माहौल विगड़ और लोगों को उकसाने का काम हुआ। शरजील इमाम ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान ऐसे भाषण दिए, जिसने हिंसा भड़काने का काम किया। शरजील इमाम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। दिल्ली पुलिस ने 2020 दिल्ली दंगों में शामिल एक्टिविस्ट उमर खालिद,



सुप्रीम कोर्ट में कहा-ये सरकारी पैसों से डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, फिर दंगे करते हैं

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

CMYK

सैन्य क्षमता बढ़ाना जरूरी

अमेरिका ने भारत के लिए दरियादिली का रास्ता खोला है, या जबरदस्ती कर्ज में फंसाने की चाल चली है, यह तो बाद में पता चलेगा। ट्रम्प ने भारत के लिए हथियारों के दरवाजे खोल दिए हैं। भारत अब यूएस से 93 मिलियन डॉलर (8249379000 रुपये) के हथियार खरीदेगा। इस डील के बाद अब भारत को जेवलिन एंटी-टैंक मिसाइलों और एक्सकैलिबर प्रिसिजन-गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स का नया बैच मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ये डील चीन और पाकिस्तान के लिए भारी भविष्य होगा। डील में मिलने वाले हथियारों से दोनों देशों की रातों की नींद उड़ जाएगी। दुश्मन के टैंक के लिए तो ये तबाही साबित होंगे। ये अमेरिका की चाल है या भारत अपने रक्षा सिस्टम में बढ़ोतरी करना चाहेगा, क्योंकि आज दुनिया विश्वयुद्ध के मुहाने पर खड़ी है। भारत के एक तरफ चीन और पाकिस्तान हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश है। इसलिए हमें अभी से चौकन्ना रहना है। इसका नतीजा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए पाकिस्तानी सेना के हमले से निकला है। अगर भारत के पास रूस का एस-400 एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं होता, तो भयंकर परिणाम हो सकते थे। इसलिए भारत को अपनी सेना को ताकत बढ़ाना आज के समय में जरूरी है। भारत को यह देखना होगा कि उसे अमेरिका ने हथियार देने का जो रास्ता खोला है, वह कहीं कुटिल चाल न हो। अमेरिकी एजेंसी डीएससीए ने अपने बयान में कहा है कि प्रस्तावित बिक्री से भारत की मौजूदा और भविष्य के खतरों का सामना करने की क्षमता में सुधार होगा। देश की सुरक्षा मजबूत होगी और क्षेत्रीय खतरों को रोका जा सकेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत को इन चीजों और सेवाओं को अपनी सेना में शामिल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अमेरिका ने एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी राउंड की बिक्री को भी मंजूरी दी है। इसकी कीमत लगभग 47 मिलियन डॉलर है, जिससे कुल कीमत लगभग 93 मिलियन डॉलर हो गई है। बता दें कि जेवलिन सिस्टम आर्टीएक्स और लॉकहीड मार्टिन ने मिलकर बनाए हैं, जिससे पैदल सेना को यूनिट लंबी दूरी पर बखरबंद टारगेट पर बहुत सटीकता से हमला कर सकती हैं। एक्सकैलिबर राउंड आर्टिलरी यूनिट के लिए लॉन्ग-गाइडेड सटीकता देते हैं, यह एक ऐसी क्षमता है जिसका इस्तेमाल भारत पहले भी कोलेटरल डैमेज को कम करने के लिए कर चुका है। डीएससीए ने इन प्रस्तावों को ट्रांसफर करने के बारे में औपचारिक तौर पर जानकारी साझा की है। भारत को इन सभी सैन्य हथियारों को अपनी सेना में शामिल करने में किसी भी प्रकार की मुश्किल नहीं होने वाली है। इस उपकरण की प्रस्तावित बिक्री से क्षेत्र में बुनियादी सैन्य संतुलन में कोई बदलाव नहीं आएगा। जेवलिन दुनिया की सबसे एडवांस पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है। एक बार फायर हो जाने के बाद सैनिक को निशाना बनाए रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह मिसाइल खुद लक्ष्य को ढूँढती है और टारगेट करती है। इससे पहले भारत फ्रांस से राफेल फाइटर खरीद चुका है, जो दुश्मन पर भारी पड़ रहे हैं। हमारे देश की सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। सरकार को चाहिए कि देश को सेना नंबर एक पर आ जाए, तो फिर कोई भी आंख उठाने की जुरत नहीं कर सकेगा। क्योंकि अभी चीन और पाकिस्तान समय-समय पर भारत को आंख दिखाते रहे हैं। कुल मिलाकर जब सभी देश अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं, तो भारत पीछे क्यों रहे, लेकिन खरीदारी भी संयम के साथ करनी होगी, जिससे देश के विपक्ष और जनता में सकारात्मक संदेश जा सके।

भारत के लिए चिंताजनक रिपोर्ट

अमेरिका-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग की हाल में आई वार्षिक रिपोर्ट को भारत के लिए चिंताजनक है, इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अपना रख स्पष्ट करना चाहिए, उक्त रिपोर्ट करीब 800 पेज की है और इसके पृष्ठ 108 और पृष्ठ 109 में दिए उल्लेख आश्चर्यजनक और समझ से परे हैं, रिपोर्ट में अहम आतंकियों को पाकिस्तान द्वारा आयोजित विद्रोही हमला बताया गया है, रिपोर्ट में इसके बाद चार दिन चले संघर्ष में भारत पर पाकिस्तान की सैन्य सफलता बताया गया है, क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे।

-जयराम रमेश
प्रमुख, कांग्रेस संचार विभाग



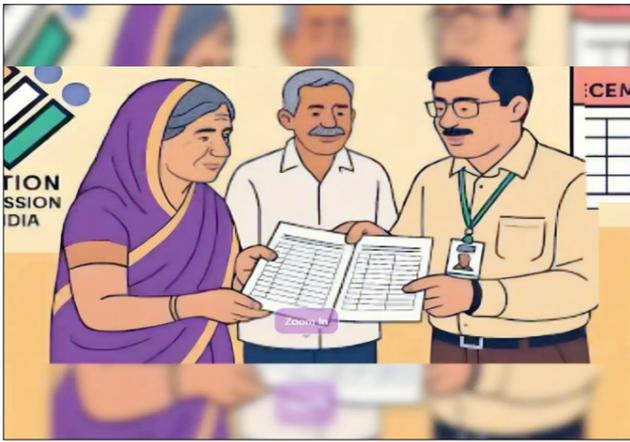
एस आई आर क्यों? इस सवाल का कोई मतलब नहीं। इस सवाल का भी कोई मतलब नहीं कि बिहार के बाद सिर्फ 12 राज्यों में ही एस आई आर क्यों? म्यांमार, जहां से सर्वाधिक रोहिंग्या घुसपैठ कर सीमावर्ती भारतीय प्रदेशों में विराजमान हैं जैसा कि कहा जाता है, लेकिन म्यांमार के सीमावर्ती भारतीय प्रदेशों में एस आई आर की जरूरत चुनाव आयोग ने बिल्कुल नहीं महसूस की। यह तय है कि विपक्ष कितना भी चिल्ल पाए कर ले यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव और 2029 में लोकसभा चुनाव एस आई आर के जरिए परिवर्तित वोट लिस्ट से ही होना है। दरअसल चुनाव आयोग आगामी इसी चुनाव की बिसात बिछा रहा है।

एसआईआर की विसंगतियां हजार हैं। जैसे बीएलओ जिन्हें एसआईआर फार्म घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी है, वह लगभग नहीं हो रहा है। जागरूक लोगों को बीएलओ को ढूँढ कर एसआईआर फार्म लेना पड़ रहा है। राजस्थान से लेकर यूपी में ऐसे हजारों उदाहरण मौजूद हैं। यूपी के एक भाजपा विधायक के वायरल वीडियो पर यकीन करे तो वह अपने लोगों से बहुत साफ शब्दों में कह रहा है कि विपक्षी वोटों के नाम उड़ा दिए जाएं। दरअसल चुनाव आयोग की मंशा भी यही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलायाए लेकिन क्या हुआ, किसने सुनी उनकी बात? उल्टे 272 पूर्व जज और नौकरशाहों ने राहुल के खिलाफ चिट्ठी लिखकर विरोध जताया कि वे चुनाव आयोग जैसे पवित्र संस्था को बदनाम कर रहे हैं। इन नौकरशाहों को ब्राजील की मॉडल का भारतीय वोट लिस्ट में शामिल होकर कई जगहों पर मतदान करना गलत नहीं लगा और न ही बिहार में वीच चुनाव सरकारी खजाने से लाखों महिलाओं को दस दस हजार की इमदद भी अर्चभित नहीं किया। जब दो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त मौजूदा चुनाव आयोग दिशा हीन बता रहा है तब लोकसभा में बहुमत के आंकड़े के बराबर 272 पूर्व नौकरशाहों का राहुल के खिलाफ खुलकर आना हैयान करने वाला है। तो क्या पूर्व नौकरशाहों के खुला विरोध को राहुल के खिलाफ महाभियोग माना जाए?

इधर चुनाव आयोग खुलकर सत्ता पक्ष के लिए यूपी विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव की बिसात बिछा रहा है उधर विपक्ष बैठकें करने में व्यस्त है। बड़ा सवाल यह है कि जब एसआईआर चल रहा है तब विपक्ष के लोग कहाँ हैं? बात केवल यूपी की करें तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि एसआईआर एक

बहरहाल चुनाव चाहे किसी राज्य की सरकार का हो या केंद्र की सरकार का, हर राजनैतिक दल मतदाताओं को लुभावने की मंशा से ऐसे कई वादे करते हैं जो वास्तव में सच नहीं किए जाते। यदि जनता को चुनावों में किए गए वादों और उन्हें पूरा किए जाने के अंतर को देखा जाए तो यह अंतर काफी बड़ी संख्या में पाया जाएगा। चुनावों से पहले ऐसे वादे हर राजनैतिक दल द्वारा किए जाते हैं। जिस तरह बिहार की जनता ने एक बार फिर से नितीश कुमार में अपना विश्वास जताया है उससे यह बात तो तय है कि जनता को किए गए चुनावी वादे काफी लुभावने थे। परंतु मतदाताओं यह सोचना होगा कि वादों की सूची और उन्हें पूरा करने में जिस भी दल का अंतर सबसे कम हो वही दल जनता के हित को सोचता है, तभी उसी दल को चुना जाता है।

SIR सिर्फ आरोप से काम नहीं चलेगा



पक्षीय चल रहा है। बीएलओ से लेकर सरकारी अमला, भाजपा और संघ के लोग सब इसमें शामिल है, लेकिन यह सब आसानी से होने क्यों दिया जा रहा है? सरकारी अमला तो सरकार के लोग होते हैं, वे वही करेंगे जो सरकार चाहेगी। और यह आज की बात नहीं है। पहले भी सरकारें ऐसे ही करती रही हैं, लेकिन सत्ता में विराजमान राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं के समतुल्य विपक्षी दलों के लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? यूपी में प्रमुख विपक्षी दल सपा है। आगामी विधानसभा चुनाव में इसे सत्ता के लिए जग करनी है, लेकिन यह पार्टी भी पूरे यूपी में कुछ जगहों को छोड़ कर एस आई आर को लेकर शायद ही कहीं और दिख रही हो। हां वाट्सएप पर इनके ज्ञान की भरमार है। वे जानते हैं कि उनके कोरे वोट कौन हैं और इन्हीं वोटों को सहेजने में वे विफल हो रहे हैं। दूसरी पार्टी कांग्रेस है। यूपी के लिए फिलहाल इसकी बात ही क्या करना। इसी मुद्दे को लेकर हाल ही उसकी दिल्ली में हाई लेवल की बैठक हुई, इस बैठक में जो भी निर्णय लिए गए हों, उसका धरातल पर उतरना आसान नहीं है। यूपी में कांग्रेस के अभी छह सांसद हैं। सपा के साथ मिलकर 17 सीटों पर लड़ें। हारी हुई सीटों पर भी कांग्रेस की स्थिति सम्मान जनक थी। विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ दो विधायक हैं।

एसआईआर को लेकर यह दो विधायक कितना कुछ कर पाएंगे, बताने की जरूरत नहीं। यहां संगठन भी हवा-हवाई है। जिला कमिटी को छोड़ दीजिए बाकी ब्लाक स्तर की कमिटीयों कहने भर को है। प्रेसशुभ में एसआईआर को लेकर इक्का-दुक्का जिला अध्यक्ष ही सक्रिय हैं बाकी सब के सब सुषुप्तावस्था में हैं। न्याय पंचायत और बृथ स्तर पर इनका कुछ नहीं है। चुनाव आयोग ने व्यवस्था दी है कि सरकारी बीएलओ के अलावा राजनीतिक पार्टियां अपना बीएलओ भी नियुक्त कर सकती हैं ताकि चुनाव आयोग पर वोट काटने और जोड़ने का तोहमत न लगे। कांग्रेस इसमें भी सुस्त है। एसआईआर को लेकर विपक्ष के लापरवाह व सुस्ती का फायदा सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता खूब उठा रहे हैं। वे सक्रिय हैं तो अपनी वाली कर रहे हैं, विपक्ष को सक्रिय होने से कौन रोका है? विपक्ष यह समझने की भूल कर रहा है कि यह सामान्य एस आई आर नहीं है। इस एस आई आर का मूल सिद्धांत ही कुछ और है। बिहार चुनाव में बुरी तरह पराजित कांग्रेस इस खुशफहमी में हो सकती है कि वहां सर्वाधिक 65 लाख वोट आउट किए जाने के बाद भी उसे औसतन करीब 71 हजार वोट प्रति विधानसभा सीट हासिल हुए, वह भी तब जब ओवैसी से लेकर बसपा, जन सुराज, आम आदमी पार्टी सहित अन्य छोटी



यशोदा श्रीवास्तव

चुनाव आयोग खुलकर सत्ता पक्ष के लिए यूपी विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव की बिसात बिछा रहा है उधर विपक्ष बैठकें करने में व्यस्त है। बड़ा सवाल यह है कि जब एसआईआर चल रहा है तब विपक्ष के लोग कहाँ हैं? बात केवल यूपी की करें तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि एसआईआर एक पक्षीय चल रहा है। बीएलओ से लेकर सरकारी अमला, भाजपा और संघ के लोग सब इसमें शामिल है, लेकिन यह सब आसानी से होने क्यों दिया जा रहा है? सरकारी अमला तो सरकार के लोग होते हैं, वे वही करेंगे जो सरकार चाहेगी। और यह आज की बात नहीं है।

पार्टियां महागठबंधन को ही नुकसान पहुंचाने के लिए ही चुनाव मैदान में थीं। आखिर यह पार्टियां तो यूपी विधानसभा चुनाव में भी होंगी और लोकसभा चुनाव में भी। आखिर इनसे निपटने या मैनेज करने का प्लान कांग्रेस के पास क्या है? दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी से सवाल किया कि बिना संगठन के हम क्या करें? धरातल पर कोई संगठन ही नहीं है। बैठक में निसंदेह और लोगों ने भी ऐसा ही महसूस किया होगा, लेकिन कांग्रेस आलाकामन शादी डॉट काम के जरिए कांग्रेस की रणनीति कार का हिस्सा बन बैठे लोगों के अलावा और किसी की सुनने तक न। कांग्रेस वर्किंग कमिटी के सदस्यों पर गौर करें तो वह पूरा का पूरा दक्षिण भारतीयों के कब्जे में है। कांग्रेस वर्किंग कमिटी में करीब दो सौ सदस्य दक्षिण भारत से ही हैं। इसके अलावा ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो या तो भाजपा नेताओं से गलबहियां करते घूम रहे हैं या फिर बिना धरातल पर झांके कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता में वापसी का ख्वाब दिखा रहे।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

क्यों उठ रहे चुनाव आयोग पर सवाल



रजनीश कपूर

हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव आयोग की भूमिका और उस पर उठते सवालों ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर बहस छेड़ दी है। एनडीए की ऐतिहासिक जीत और महागठबंधन (इंडिया एलायंस) की करारी हार के बीच, मुख्य सवाल यही उठा कि क्या चुनाव आयोग ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का सही तरह से निर्वहन किया? साथ ही, आचार संहिता के उल्लंघन, राजनीतिक दलों के आचरण और आयोग पर दोहरे मानदंडों के आरोपों ने भी चुनावी निष्पक्षता की मूल भावना को चुनौती दी है। हाल के चुनावों में चुनाव आयोग पर पक्षपात और दोहरे मानदंड अपनाएने के आरोप लगे। खास तौर पर, कांग्रेस और महागठबंधन ने वोट लिस्ट, अधिकारियों की नियुक्ति और निष्पक्ष मतदान पर गंभीर सवाल खड़े किए। आरोप है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में वोट लिस्ट से लाखों नाम हटा दिए गए या मनमाने ढंग से जोड़े-घटाए गए।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आयोग ने भाजपा शासित राज्यों से चयनित नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों को चुनावी पर्यवेक्षक नियुक्त कर पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाया। विपक्ष ने मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि आयोग की प्रक्रिया आम जनता का भरोसा कायम नहीं रख पा रही है। इस चुनाव में लगभग सभी प्रमुख दलों के सोशल मीडिया पर भड़काऊ, जातिवादी और भ्रामक कंटेंट साझा होने के आरोप लगे। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ऐसे लगभग 21 एफआईआर दर्ज किए, जिनमें भाजपा, राजद और कांग्रेस जैसे बड़े दलों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। कई सोशल मीडिया हैंडलस पर तो गुमराह करने वाले AI-जनित वीडियो और डीपफेक कंटेंट डालने के आरोप मिले, जिन्हें तुरंत हटवाया गया। आयोग द्वारा आचार संहिता के पालन के लिए सोशल मीडिया पर निगरानी करने की व्यवस्था थी, परंतु बड़ी संख्या में भड़काऊ और गुमराह करने वाले पोस्ट सामने आए, जिससे आयोग की प्रभावशीलता को लेकर सवाल भी उठे। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग की सबसे अहम जिम्मेदारी है, चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना। आयोग को अपने हर कदम पर समानता और पारदर्शिता का पालन करना चाहिए। आयोग की साख को बहाल करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए। जैसे कि सभी दलों की शिकायतों की सार्वजनिक व स्वतंत्र जांच। पर्यवेक्षकों और चुनावी कर्मियों की निष्पक्ष नियुक्ति जो

कि राजनीतिक झुकाव से दूर रहते हुए की जाए। वोट लिस्ट की शुद्धता और अद्यतन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना। सोशल मीडिया व डिजिटल प्रचार पर कठोर निगरानी और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई। आचार संहिता उल्लंघन पर बिना किसी भेदभाव के उचित व सख्त न्यायिक कार्रवाई। वहीं देखा जाए तो महागठबंधन (इंडिया एलायंस) रणनीतिक स्तर पर संगठित नहीं हो सका। सीट शेयरिंग, यानी सीटों का बंटवारा, चुनाव से ठीक पहले तय हुआ, जिससे अभियान की गति और एकता दोनों प्रभावित रहें। तेजस्वी यादव के देर से सक्रिय चुनाव प्रचार, गठबंधन में सहयोगी दलों के मतभेद और साझा विजन की कमी ने विपक्ष की प्रभावशीलता कम कर दी। साथ ही, कांग्रेस जैसी सहयोगी दल जमीनी स्तर पर मतदाताओं को लाम बंद करने में नाकाम रही। ऐसे समय में जब एनडीए अपनी एकचुटता दिखा रहा था, महागठबंधन अपनी आंतरिक समस्याओं में उलझ कर रह गया। महागठबंधन ने मुख्य रूप से सत्ता विरोधी लहर (एंटी-इन्कम्बेंसी) पर ज्यादा दांव लगाया, जबकि एनडीए ने अपनी स्थिरता, विकास, और समावेशिता के एजेंडा के साथ मतदाताओं को बेहतर तरीके से साधने में सफल रहा। जातिगत समीकरणों को लेकर महागठबंधन ने पारंपरिक रणनीति अपनाई, परंतु दलित, महिला, और अति पिछड़ा वर्गों को खास तौर पर टारगेट करके एनडीए ने अपने पुराने वोट बैंक के दायरे को काफी विस्तार दिया।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

मनोरंजन से मानसिक क्रांति तक: टीवी का बदला चेहरा

ठे लैक एंड व्हाइट बुद्ध बक्स (टेलीविजन) अपने सहज प्रस्तुतिकरण के दौर से गुजरते हुए एक आधुनिकता के साथ कदमताल करते हुए सूचना क्रांति का सबसे बड़ा हथियार और हर घर की अहम जरूरत बन गया, पता ही नहीं चला। यह दुनिया जहान की खबरें देने और राजनीतिक गतिविधियों की सूचनाएं उपलब्ध कराने के अलावा मनोरंजन, शिक्षा तथा समाज से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं को उपलब्ध कराने, प्रमुख आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समूचे विश्व के ज्ञान में वृद्धि करने में मदद करने वाला एक सशक्त जनसंचार माध्यम है। यह संस्कृतियों और रीति-रिवाजों के आदान-प्रदान के रूप में मनोरंजन का सबसे सस्ता साधन है, जो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी दुनिया के ज्ञान में असम वृद्धि करने में मददगार साबित हो रहा है। मानव जीवन में टीवी की बढ़ती भूमिका तथा इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 21 नवम्बर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है।



सूचना के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति का आविष्कार माना गया है, जिसके जरिए समस्त दुनिया हमारे करीब रह सकती है और हम अब घर बैठे ही दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली घटनाओं को लाइव देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार 21 तथा 22 नवम्बर 1996 को विश्व टेलीविजन मंच का आयोजन करते हुए टीवी के महत्व पर चर्चा करने के लिए मीडिया को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया था। उस दौरान विश्व को परिवर्तित करने में टीवी के योगदान और टीवी के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में व्यापक चर्चा की गई थी। उसी के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में 17 दिसम्बर 1996 को एक प्रस्ताव पारित करते हुए प्रतिवर्ष 21 नवम्बर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाए का निर्णय

लिया गया और तभी से प्रतिवर्ष 21 नवम्बर को ही यह दिवस मनाया जाता रहा है। इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन का आविष्कार 1927 में हुआ माना जाता है और उसके करीब 32 साल बाद इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन ने भारत में पहला कदम रखा। भारत में टीवी का पहला प्रसारण प्रायोगिक तौर पर दिल्ली में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना के साथ 15 सितम्बर 1959 को शुरू किया गया। उस समय टीवी पर सप्ताह में केवल तीन दिन ही मात्र तीस-तीस मिनट के कार्यक्रम आते थे, लेकिन इतने कम समय के बेहद सीमित कार्यक्रमों के बावजूद भी टीवी के प्रति लोगों का लगाव बढ़ता गया और यह बहुत जल्द लोगों की आदत का अहम हिस्सा बन गया। दूरदर्शन का व्यापक प्रसार हुआ वर्ष 1982 में दिल्ली में हुए एशियाई खेलों के आयोजन के प्रसारण के बाद। दूरदर्शन द्वारा अपना दूसरा चैनल 26 जनवरी 1993 को शुरू किया गया और उसी के बाद दूरदर्शन का पहला चैनल डीडी-1 और दूसरा नया चैनल डीडी-2 के नाम से लोकप्रिय हो गया, जिस बाद में डीडी मेट्रो नाम दिया गया। वहीं ही टीवी के आविष्कार के इन दशकों में इसका स्वरूप और तकनीक पूरी तरह बदल चुकी है लेकिन इसके



योगेश कुमार गौयल

कार्य करने का मूलभूत सिद्धांत अभी भी पहले जैसा ही है। हालांकि किसी भी वस्तु के अच्छे और बुरे दो अलग-अलग पहलू ही हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही सूचना एवं संचार क्रांति के अहम माध्यम टीवी के मामले में भी है। एक ओर जहां यह मनोरंजन और ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है और नवीनतम सूचनाएं प्रदान करते हुए समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, वहीं इसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आते रहे हैं। टेलीविजन की ही वजह से ज्ञान, विज्ञान, मनोरंजन, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि तमाम क्षेत्रों में बच्चों से लेकर बड़ों तक की सभी जिज्ञासाएं शांत होती हैं। अगर नकारात्मक पहलुओं की बात करें तो टीवी के बढ़ते प्रचलन के साथ-साथ इस पर प्रदर्शित होते अश्लील, हिंसात्मक, अंधविश्वासों का बीजारोपण करने तथा भय पैदा करने वाले कार्यक्रमों के कारण हमारी संस्कृति, आस्था और नैतिक मूल्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

समुद्र में आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा पाकिस्तान

आइलैंड तेल के 25 कुएं खोदे जाएंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के समर्थन के बाद उठाया कदम

इस्लामाबाद। पाकिस्तान पहलीसमूद्र में आर्टिफिशियल आइलैंड (कृत्रिम द्वीप) बनाने जा रहा है। शहबाज सरकार ने अरब सागर में इस आइलैंड को बनाने की मंजूरी दे दी है। इसे समुद्र में तेल की खोज (आयल एक्सप्लोरेशन) के लिए स्थाई प्लेटफार्म की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड (पीपीएल) लीड करेगी।



ट्रम्प ने जुलाई में एलान किया था: अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के बड़े तेल भंडार विकसित करेंगे

दूर, सुजावल इलाके के पास बनाया जा रहा है। सुजावल कराची से लगभग 130 किमी दूर है। आइलैंड को समुद्र की ऊंची लहरों से बचाने के लिए 6 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है। पहले समुद्री लहरों की वजह से जिन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स में रुकावट आई थी, उन्हें दूर किया जा सकेगा। आइलैंड के फरवरी तक तैयार होने की उम्मीद है। भारी मशीनरी और सप्लाय को एक स्थिर प्लेटफार्म से संचालित करने से खर्च में लगभग 33 प्रतिशत तक कमी हो सकती है। पहले मौसम के कारण बार-बार देरी होती थी, जिससे लागत बढ़ जाती थी।

पीपीएल के मुताबिक यहाँ 24 घंटे ड्रिलिंग चल सकेगी। पाकिस्तान की समुद्री सीमा में पिछले साल सितम्बर में तेल और गैस का एक बड़ा भंडार मिला था। डान की रिपोर्ट मुताबिक, पाकिस्तान ने इस इलाके में एक सहयोगी देश के साथ मिलकर 3 साल तक खोज किया था। इसके बाद यहाँ तेल और गैस रिजर्व की मौजूदगी की पुष्टि हुई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह भंडारिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार हो सकता है। फिलहाल वेनेजुएला में तेल का सबसे बड़ा रिजर्व है, जहाँ 34 लाख बैरल तेल है। वहीं, अमेरिका के पास सबसे बड़ा तेल का भंडार है, जिसे अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया। पाकिस्तान अगर तेल और गैस को निकालने में कामयाब हो गया तो यह उसकी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, भंडार से जुड़ी रिसर्च पूरी करने में करीब 42 हजार करोड़ का खर्च आएगा। इसके बाद समुद्र की गहराई से इस निकालने में 4-5 साल लग सकते हैं। अगर रिसर्च सफल रही तो तेल और गैस को निकालने के लिए कुएँ लगाने और बाकी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में और ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। पाकिस्तानी अधिकारियों ने तेल और गैस भंडार मिलने को देश की 'ब्लू वाटर इकोनॉमी' के लिए अच्छा बताया है। समुद्री संपदा, नए बंदरगाहों और सामुद्रिक नीति (मेरीटाइम पॉलिसी) के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ही ब्लू इकोनॉमी कहलाता है। पाकिस्तान विश्व में कच्चे तेल के भंडार में 50वें स्थान पर है।



नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण धुंध के बीच सड़क पर वाहन चलते हुए।

वियतनाम में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हुई

हानोई। वियतनाम के मध्य क्षेत्र में भारी बारिश एवं बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है जबकि पांच अन्य लोग लापता हैं। यह जानकारी वियतनाम आपदा और ड्राइक प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को दी। रिपोर्ट के अनुसार, 43200 से अधिक घर जलमग्न हो गए हैं जबकि 91 अन्य क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ के कारण 10000 हेक्टेयर से अधिक धान एवं अन्य फसलें जलमग्न हो गई हैं तथा 6500 से अधिक पशुधन और मुर्गियों की मौत हो गई है। यह बारिश, बिजली की कटौती होने से 553200 से अधिक घर प्रभावित हुए हैं।

अमेरिकी सैन्य अधिकारी संघर्ष समाप्त पर वार्ता के लिए यूक्रेन पहुंचे

वाशिंगटन। पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए यूक्रेन पहुंचे। यह जानकारी बोबोसी ने शुक्रवार को अमेरिकी सेना के हवाले से दी। अमेरिकी सेना के सचिव डैन ड्रिस्कॉल को नेतृत्व में टीम की आज कोव में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेन्स्की से मिलने की उम्मीद है जब वे तुर्की की यात्रा से लौटेंगे। बुधवार से ऐसी खबरें प्रसारित हो रही हैं कि अमेरिका और रूस ने एक नई शान्ति योजना तैयार की है जिसमें यूक्रेन को बड़ी रियायतें देने की बात की गई है लेकिन न तो वाशिंगटन और न ही मास्को ने इस योजना की आधिकारिक पुष्टि की है। इससे पहले, यूक्रेन के पश्चिमी शहर टेनोपिल पर रूसी मिसाइल एवं ड्रोन हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए थे। रूस ने 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण शुरू किया था। सेना के प्रवक्ता कर्नल डेविड बटनर ने एक बयान में कहा कि सचिव ड्रिस्कॉल और उनकी टीम प्रशासन की ओर से आज सुबह कोव पहुंचे, ताकि वे यूक्रेनी अधिकारियों से मुलाकात कर सकें और युद्ध समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा कर सकें।

दावा: ऑपरेशन सिंदूर में पाक ने भारत को हराया

अमेरिकी रिपोर्ट में पहलगांम अटैक को भी आतंकी अटैक न मानकर विद्रोही हमला माना गया

वाशिंगटन। एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की लड़ाई (ऑपरेशन सिंदूर) में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी मिली थी। इस रिपोर्ट में पहलगांम अटैक को भी आतंकी हमला न मानकर विद्रोही हमला माना गया है। 800 पनौतों की इस रिपोर्ट को यूएस-चाइना इकोनॉमिक एंड सिस्वोरिटी रिव्यू कमीशन (यूएससीसी) ने जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने कम से कम 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को गिराया, जिनमें राफेल जेट भी शामिल हैं।

रिपोर्ट को यूएस-चाइना इकोनॉमिक एंड सिस्वोरिटी रिव्यू कमीशन (यूएससीसी) ने किया जारी

हथियारों का इस्तेमाल किया और अपने सैन्य फायदे को दुनिया के सामने रखा। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने चीन के एचआईक्यू-9 एयर डिफेंस सिस्टम, पीएल-15 मिसाइलें और जे-10 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। भारत का दावा है कि पाकिस्तान को इस दौरान चीन से खुफिया जानकारी (इंटेलिजेंस) भी मिली। हालांकि पाकिस्तान ने इसे नकार दिया और चीन ने इस पर कुछ भी साफ नहीं कहा। रिपोर्ट के मुताबिक 2019/2023 के बीच पाकिस्तान के 82 प्रतिशत हथियार चीन से आए हैं। 90 के आखिरी दशक में जब चीन बहुत तेजी से आर्थिक और तकनीकी तौर पर ताकतवर हो रहा था तो अमेरिका में इसे लेकर चिंता बढ़ी। अमेरिकी नेता यह मानने लगे कि चीन से आने वाले आर्थिक फायदे और सुरक्षा खतरों दोनों को साथ-साथ समझना ही तकनीकी ताकतविरुद्ध अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं बन रही, यूएससीसी खुद कोई कार्रवाई नहीं करती, बस रिपोर्ट बनाकर अमेरिका को संसद को देती है। आयोग की सिफारिशों को अंतिम

ट्रम्प बोले: 350 प्रतिशत की धमकी पर मोदी का फोन आया

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि उन्होंने 350 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी देकर भारत-पाकिस्तान के बीच जंग रूकवाई थी। ट्रम्प ने अमेरिका-सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में कहा कि मुझे सबसे पहले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का फोन आया था। उन्होंने शुकिया कहा और बताया कि मैंने लाखां जाने बचाई हैं। इसके बाद ट्रम्प ने दावा किया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया। मोदी ने कहा कि हम खत्म कर चुके हैं। ट्रम्प ने पूछा कि क्या खत्म कर चुके हो? इस पर मोदी ने बताया कि हम जंग नहीं करने जा रहे हैं। पहलगांम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस दौरान पाकिस्तान में आतंकी टिकानों निशाना बनाया गया। 10 मई को दोनों देशों के बीच सीजफायर हुआ। ट्रम्प ने 60 से ज्यादा बार जंग रूकवाने का दावा किया ट्रम्प ने ही सबसे पहले सोशल मीडिया पर सीजफायर की जानकारी दी थी। उन्होंने ये दावा किया था कि उनकी वजह से ही संघर्ष थमा है।



रिपोर्ट में शामिल करने के लिए, उन्हें कम से कम 8 सदस्यों (दो-हिंडाई) के समर्थन की जरूरत होती है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यूएससीसी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। अखबार लिखता है कि यूएससीसी ने एक बार फिर से चीन की आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा क्षेत्र में जो रूढ़ी तरक्की को पैसे दिखाया गया है कि जैसे वह दुनिया के लिए खतरा हो। अभी का रवैया दिखाता है कि यह रिपोर्ट राजनीतिक मकसद से लिखी गई है और हकीकत का पूरी निष्पक्षता से विश्लेषण नहीं करती। आयोग के भीतर चीन को लेकर भारी गलतफहमियाँ और अहंकार मौजूद है। अखबार आगे लिखता है कि अमेरिका को चीन को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। अखबार का कहना है कि चीन की हथियार इंडस्ट्री के विकास को लेकर आरोप लगाना या उसे गलत तरीके से पेश करना, किसी भी संप्रभु देश के अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने के मूल अधिकार को नकारने जैसा है। अखबार ने लिखा-अमेरिका सपनाई चैन को हथियार जैसे इस्तेमाल करता है।

जूनियर ट्रम्प ने ताजमहल देखा

आगरा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे जूनियर ट्रम्प ताजमहल देखने के लिए गुरुवार को आगरा पहुंचे। जूनियर ट्रम्प अपनी पत्नी और कुछ दोस्तों के साथ ताज महल का दौरा करने के लिए करीब साढ़े तीन बजे पहुंचे और डेढ़ घंटे तक ताजमहल के अंदर रहे।



ताजमहल के अंदर डायना टेबिल पर फोटो सेशन कराया। गाइड नितिन सिंह ने जूनियर ट्रम्प को ताजमहल का दौरा कराया। गाइड नितिन सिंह ने डोनाल्ड ट्रम्प को भी ताजमहल का दौरा कराया था। जूनियर ट्रम्प की सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए थे। आगरा आने पर स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। कई थानों का फोर्स लगाई गई थी। इसके अलावा स्थानीय सूचना तंत्र भी महल देखने पहुंचे थे।

दक्षिण कोरिया में 267 यात्रियों को ले जा रही नौका समुद्र में फंसी, कोई हताहत नहीं

सोला। दक्षिण कोरिया के पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में बुधवार को 267 यात्रियों को ले जा रही एक यात्री नौका फंस गई। समाचार एजेंसी योनहास ने यह जानकारी दी। स्थानीय समाचारनुसार कल रात 8:17 बजे (117 जीएमटी) तट रक्षक बल को सूचना मिली कि 246 यात्रियों और 21 चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही नौका राजधानी सोल से लगभग 310 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थितान काउंटी के एक द्वीप के पास फंस गई है। यह नौका दक्षिणी रिसेंट द्वीप जेजू से रवाना होकर दक्षिण-पश्चिमी बंदरगाह शहर मोकोपो की ओर जा रही थी। कथित तौर पर जहाज द्वीप के पास पहुंचते समय एक डूबी हुई चट्टान से टकरा गया।

आईईए ने ईरान से हमलों में प्रभावित सभी परमाणु प्रतिष्ठानों तक पहुंच प्रदान करने का किया आग्रह

वियना/तेहरान। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने आज चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जून में हुए हमलों में क्षतिग्रस्त ईरानी प्रतिष्ठानों तक उसकी अभी भी महत्वपूर्ण पहुंच नहीं है और तेहरान को संबंधित यूरेनियम भंडार के सत्यापन को बहुत देर हो चुकी है। वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को संबोधित करते हुए महानिदेशक राफेल ग्रासी ने बुधवार को कहा कि एजेंसी को ईरान के निम्न और उच्च संबंधित यूरेनियम के भंडार की तत्काल जांच करने की आवश्यकता है, जिसे निरीक्षण पिछले पांच महीनों से सत्यापित नहीं कर पाए हैं। ग्रासी ने कहा कि सितम्बर में काहिरा में

तेहरान के संबंधित यूरेनियम भंडार के सत्यापन को बहुत देर हो चुकी है

निरीक्षण पर सहमत होने के बाद वे ईरानी अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में हैं और समझौते का पूरी तरह से लागू करना है तो और ज्यादा रचनात्मक सहयोग की आवश्यकता है। उनकी यह दिव्यणी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन द्वारा समन्वित प्रयास के साथ मेल खाती है जिन्होंने संयुक्त रूप से एक मसौदा प्रस्ताव में मांग किया है कि ईरान आईईए के साथ अपना पूर्ण सहयोग फिर से शुरू करे तथा निरीक्षणों को अप्रतिबंधित पहुंच प्रदान करे। हालांकि तेहरान ने चेतावनी दी है कि इस तरह के

प्रस्ताव से आईईए निदेशक के साथ सितम्बर में हुई सहमति खतरे में पड़ जाएगी। इस सप्ताह की शुरुआत में, ईरान के उप विदेश मंत्री काज़म गुरीबाबादी ने पश्चिमी देशों की आलोचना करते हुए कहा था कि उनके कार्यों से समझौते को नुकसान पहुंच सकता है। ईरानी अधिकारियों ने इस रुकावट को सितम्बर के आखिर में सैन्यबैक मैकेनिज्म के तहत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के फिर से लागू होने पर जोर दिया। आर्थिक रूप से सार्वजनिक की गई आईईए रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने अभी भी निरीक्षणों को जून में 12 दिनों के संघर्ष के दौरान इजरायल और अमेरिकी हमलों में क्षतिग्रस्त हुए परमाणु स्थलों का दौरा करने की अनुमति नहीं दी।

सऊदी अरब-अमेरिका के बीच 575 अरब डॉलर के समझौते

दोहा। सऊदी अरब के निवेश मंत्री खालिद अल-फलीह ने कहा है कि इस सप्ताह नए सौदों की घोषणा के बाद वर्ष 2025 में अमेरिका और सऊदी अरब की कंपनियों के बीच हस्ताक्षरित अनुबंधों का मूल्य बढ़कर लगभग 575 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। गौरतलब है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान वहां एक निवेश मंच में हस्ताक्षरित सौदों के माध्यम से अमेरिका के प्रति प्रतिनिधियों और कंपनियों ने भाग लिया। अल-फलीह ने बुधवार को अल एखबारिया प्रसारक से कहा, सऊदी और अमेरिकी कंपनियों के बीच लगभग 267 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के 242 नए समझौतों की घोषणा की गई।

मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता विवादों में घिरी

इटली की प्रिंसेज समेत 3 जनों ने दिया इस्तीफा, आयोजक ने लगाया कंटेस्टेंट से अफेयर का आरोप

बैंकाका। ब्यूटी कान्स्टेंट मिस यूनिवर्स 2025 से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ग्रैंड फिनाले से एक दिन पहले मिस यूनिवर्स सिलेक्शन कमेटी की प्रिंसेज और इटालियन प्रिंसेज कैमिलो डि बोर्बोन ने ज्यूरी पेनल छोड़ दिया है। वह पेनल छोड़ने वाली तीसरी जज हैं। इससे पहले मशहूर म्यूजिशियन ओमार हारफूश और फ्रांस के पूर्व फुटबलर क्लाउड मार्केलेले ने भी ज्यूरी छोड़ दी थी। मिस यूनिवर्स में जर्जिन पेनल 8 सदस्यों का होता है। 3 जजों के पेनल छोड़ने के बाद आर्गनाइजेशन ने नताली ग्लेबोवा (कनाडा) की पूर्व मिस यूनिवर्स 2005) को शामिल किया है। अब पेनल में 6 सदस्य हैं। ग्रैंड फिनाले कल यानी 21 नवम्बर को थार्लैंड के राजधानी बैंकाक में होगा। ओमार ने आरोप लगाया कि जज कमेटी बनने से पहले ही आर्गनाइजर्स ने टॉप-30 कंटेस्टेंट का सिलेक्शन अनआफिशियल तरीके से कर लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे कंटेस्टेंट को चुना



गया जिनके आर्गनाइजर्स से पर्सनल रिलेशनशिप। यह है। इसके बाद मार्केलेले ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। ओमार हारफूश ने 17 नवम्बर को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मिस यूनिवर्स 2025 के आर्गनाइजर्स पर आरोप लगाते हुए लिखा था, टॉप 30 प्रतियोगियों को चुनने के लिए गलत तरीके से वोटिंग की गई। यह वोटिंग उन लोगों ने की जो पेनल के सदस्य नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि मुझे गुमराह किया गया और मुझे गलत सिलेक्शन प्रोसेस को मानने के लिए कहा गया। इसके कारण मुझे हुए इमोशनल ट्रामा भी हुआ, मेरी रेपुटेशन

डैमेज हुई। ओमार ने अपनी पोस्ट में आर्गनाइजर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की धमकी भी दी। मार्केलेले ने 18 नवम्बर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर पेनल छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अफसांस के साथ, मैं मिस यूनिवर्स 2025 में शामिल नहीं हो पाऊंगा। आपको समझ और समर्थन के लिए धन्यवाद। इसके विरोध में कई देशों की कंटेस्टेंट्स ने हाल से बाहर निकलकर विरोध जताया। नवात ने फातिमा से कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता से जुड़े प्रमोशनल कंटेस्टेंट शेरार नहीं किए। जब फातिमा ने इस पर आपत्ति जताई, तो नवात ने सुरक्षा कर्मियों को बुलाने की धमकी दी और कहा कि जो भी उनके समर्थन में आएगा, उसे प्रतियोगिता से बाहर किया जा सकता है। इसके बाद फातिमा मंच छोड़कर बाहर चली गई। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर #JusticeForFatima ट्रेंड करने लगा। विरोध के बाद नवात ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी और कहा कि अगर किसी को बुरा लगा है, तो वह माफी चाहते हैं।

चीनी वैज्ञानिकों के भरोसे चीन को टक्कर दे रहा अमेरिका

मेटा एआई टीम 11 में से 7 रिसर्चर चीन के, 1 भी अमेरिकी नहीं

वाशिंगटन। मेटा सीओओ मार्क जकरबर्ग ने जून में अपनी नई सुपर इंटेलिजेंस लैब का एलान किया था। तब उन्होंने बताया था कि इस प्रोजेक्ट में शामिल 11 वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इनका मकसद ऐसी मशीनें बनाना है जो इंसानी दिमाग से भी ज्यादा ताकतवर हों। न्यूयॉर्क टाइम्स को मिले इंटरनल मेमो से पता चला है कि ये सभी 11 वैज्ञानिक दूसरे देशों में पढ़े लिखे अप्रवासी हैं। इनमें से 7 वैज्ञानिक चीन से हैं, जबकि बाकी 4 भारत, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हैं। अखबार ने लिखा है कि अमेरिका में लंबे समय से सरकारी अधिकारियों और एक्सपर्ट को लाने के लिए मार्क जकरबर्ग ने 1.26 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे। मेटा



बड़ा खतरा बताया रहा है। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका में हो रहा बड़ा और क्रांतिकारी एआई रिसर्च काफी हद तक चीनी वैज्ञानिकों की मदद से आगे बढ़ाया जा रहा है। यह मेटा की एआई यूनिट के चीफ अलेक्जेंडर वांग है। जून 2025 में मेटा से जुड़े। इन्हें कंपनी में लाने के लिए मार्क जकरबर्ग ने 1.26 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे। मेटा

अमेरिका में हो रहा बड़ा और क्रांतिकारी एआई रिसर्च काफी हद तक चीनी वैज्ञानिकों की मदद से आगे बढ़ाया जा रहा है

पहले से ही चीनी वैज्ञानिकों को काफी निरभर रही है। कंपनी के भीतर अक्सर मजाक में कहा जाता है कि नए आने वालों को दो चीजें सीखनी पड़ती हैं। पहली हैक, यानी कंपनी की प्रोग्रामिंग भाषा और दूसरी मंदा रितन, क्योंकि एआई टीमों में बड़ी संख्या में चीनी रिसर्चर्स होते हैं। इस साल मेटा को लगभग 6300 एच-1बी वीजा अप्रूव हुए जो

अमेजन के बाद सबसे ज्यादा हैं। मेटा ने 2018 के बाद से कम से कम 28 रिसर्च पेपर पर चीनी संगठनों के साथ मिलकर काम किया है। सिर्फ मेटा ही नहीं, बल्कि ऐपल, गूगल, इंटरनेट और सेल्सफोर्स जैसी अमेरिकी कंपनियों ने भी चीनी संगठनों के साथ मिलकर कई अहम रिसर्च किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने तो सबसे ज्यादा, यानी कम से कम 92 अमेरिकी पेपरों से साझेदारी की है। अमेरिका में ट्रम्प सरकार के आने के बाद से प्रशासन सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी अपना चुका है। इसके अलावा सिलिकॉन वैली में भी चीनी विरोधी भावना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बावजूद चीनी रिसर्चर्स न सिर्फ अमेरिका में बने हुए हैं बल्कि अहम रोल भी निभा रहे हैं।

(A Minority Institution)
ISLAMIA DEGREE COLLEGE
 Deoband, Distt., Saharanpur
 (Recognized by NCTE)
 (Affiliated to SCERT Govt. of India)

D.El.Ed (B.T.C.) 2025-27

Qualification For Admission:
 ❖ 50% Marks in graduation for General Candidates/
 Other State.
 ❖ 45% Marks in graduation for OBC & SC/ST Candidates.

➤ Date of Issue of Registration Form 24/11/2025 In the College or Available on Website (Online & offline)
 ➤ Last Date For Submitting the Completed Application Form in College- 15/12/2025

Secretary Principal

काउंसिलिंग शासनादेश के अनुसार संपन्न करायी जाएगी।

Contact no. : 9045143298, 8755525452

यौन समस्याएं

यौन समस्याओं के विशेषज्ञ

पुराने से पुराने यौन रोग के मरीज एक बार अवश्य मिलें

डा. सम्राट

नशामुक्ति, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा तम्बाकू, प्रोक्सीवॉन केपसूल अपफीम, चरस, डोपे पोस्ट हजेक्शन व अन्य नशा छुड़ाने का स्थायी ईलाज।

नावल्टी सिनेमा चौक मुजफ्फरनगर (यू.पी.)

M-9412211108